External Debt Position of the Country

1842. SHRI JAGESH DESAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India's external debt is going from bad to worse according to world debt tables (1989-90) computed by the World Bank ; and

(b) if so, what steps Government propose to reduce this gradually ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) and (b) No, Sir. The level of country's external debt and likely burden of debt servicing are being constantly kept in view to ensure that they remain within manageable limits. Government have taken a number of steps to boost exports and increase invisible earnings, contain imports, improve disbursement of committed aid/loan and to ensure that dependence on external financing is contained.

प्राकृतिक विपदाओं के लिए राजस्थान में स्थापित किया गया आवर्ती कोष

1843. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार राजस्थान में प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए स्थापित किये गये आवर्ती कोष हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस कोष से धनराशि लिए जाने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक इस कोष से कितनी राशि निकाली गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष जुलाई में राजस्थान के अधिकांश जिले भयंकर अकाल और बाढ़ की चपेट में रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या पीड़ितों को इस कोष में से कोई राहत प्रदान की गई, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या इस कोष से धनराशि लेने के लिए राज्य सरकार के पास अंशदान के लिए 25 प्रतिशत राशि नहीं है यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार या यह कोष राज्य में बाढ़ या अकाल के समय राज्य सरकार को राहत प्रदान कर सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) नवें वित्त आयोग द्वारा अपनी दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत पर होने वाले व्यय को पूरा करने के वास्ते राजस्थान के लिए 1990-95 की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 124 करोड़ रुपये की राशि के संग्रह से एक आपदा राहत कोष स्थापित किया जाना है । केन्द्र सरकार इस कोष में प्रतिवर्ष 75 प्रतिशत अर्थात् 93 करोड़ रुपए का अंशदान करेगी तथा शेष राशि राज्य सरकार देगी । यह बात विचाराधीन है कि इस कोष को किस तरह स्थापित एवं प्रचालित किया जाए ।

(ग) कोष के ब्यौरे को अग्रिम रुपये दिए जाने तक राज्य सरकार को राहत उपाय करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकार को उनके अनुरोध पर चालू वर्ष में अब तक 23.25 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है ।

(घ) चालू मानसून अवधि के दौरान राज्य सरकार से राजस्थान के किसी भी हिस्से में सूखे की स्थिति के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त

नहीं हुई है । तथापि, इस अवधि के दौरान बाढ़ों से हुई क्षति के बारे में राज्य सरकार ने सूचित किया है ।

(ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने चालू मानसून अवधि के दौरान बाढ़ों से प्रभावित व्यक्तियों को अब तक 2.19 करोड़ रुपए की राहत सहायता वितरित की है ।

(च) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने चालू वर्ष में राज्य आपदा राहत निधि में राज्य के 25 प्रतिशत के अंशदान के लिए 31 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है ।

Establishment of garment export trade office in Tamil Nadu

1844. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to establish a garments export trade centre in Tamil Nadu particularly in Tirupur ; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV) : (a) to (b) Government has no proposal under consideration to establish a garments export trade centre in Tamil Nadu. However, Tirupur having developed into an important centre of knitwear industry, all efforts are being made to provide necessary facilities for further development of this industry in Tirupur.

Export of Seed Lac

1845. SHRI JAGDISH PRA SAD MATHUR : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the 'Lac Kutir Ud-yog Raksha Samiti' representing lakhs of growers and traders *of* Lac had approached Government demanding that import of seed-lac from abroad be banned and that export of Indian seed-lac be permitted at 100 per cent and it be interlinked with the export of shelac so that their interest was safeguarded;

(b) if so, what steps Government have taken in this respect ;

(c) whether recommendations of the MR. Srinivasan Committee and those of the NABARD in this regard would be implemented and if so, when ; and

(d) whether Government of Bihar had also approached the Central Government to fix profitable price of Lac ; if so, the Central Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The matter is under consideration of the Government.

Development of Places of PilgrimageIn Madhya Pradesh, Rajathanand Himachal Pradesh

1846. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of TOUPISM be pleased to state :

(a) What are the names of the pilgrimage centres proposed to be developed in Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh by Central/State Governments during the Eighth Plan period as per the proposals under examination;